माननीय न्यायमूर्ति ***मुकुल मुगल, सी.जे. & और जसबीर सिंह,*** *जे.*

विकलंग सांग, *हरियाणा, — याचिकाकर्ता*

बनाम

हरियांद की स्थिति *OTHERS, — उत्तरदाताओं*

2007 की सीडब्ल्यूपी नंबर 1420

27 मई 2010

भारत का संविधान, 1950 — अनुच्छेद 226 — व्यक्तियों के साथ विकलांगता (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 — Ss.32, 33 और 47 (2) — राज्य सरकार विकलांग व्यक्तियों को भर्ती के समय 3% आरक्षण प्रदान करनापदोन्नति में दावा आरक्षण— — केंद्र सरकार का इनकार विकलांग व्यक्तियों को प्रचार के रास्ते में 3% कोटा प्रदान करना —विकलांगों के लिए पदोन्नति में आरक्षण के लिए 1995 अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं व्यक्तियों — शब्द 'रोजगार' में 'पदोन्नति' — याचिका शामिल है अनुमति दी गई, उत्तरदाताओं ने पदोन्नति के लिए 3% पदों को आरक्षित रखने का निर्देश दिया विकलांग व्यक्तियों के लिए.

अभिनिर्धारित किया गया कि निःशक्तजन (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 47 (2) का यह अर्थ नहीं लगाया जा सकता कि निःशक्तजनों को केवल सेवा में शामिल किए जाने के प्रारंभिक चरण में ही रोजगार प्रदान किया जाए। 1995 के अधिनियम का उद्देश्य स्पष्ट है और पदोन्नति सहित कैरियर की प्रगति के लिए समान अवसर स्पष्ट रूप से विधायी अधिदेश है। उक्त प्रावधान का कोई अन्य अर्थ देने से क़ानून का उद्देश्य विफल हो जाएगा। 1995 के अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों के उपखंड (i) और (v) अधिक महत्वपूर्ण हैं क्योंकि यह राज्य से विकलांग व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने की अपेक्षा करता है। यह उन अवसरों के समानीकरण पर भी जोर

देता है जिन्हें केवल भर्ती के प्रारंभिक चरण में प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यदि राज्य की याचिका को स्वीकार किया जाता है और परोपकारी कानून को एक सीमित अर्थ दिया जाता है, तो यह प्रारंभिक भर्ती स्तर पर विकलांगों के ठहराव का कारण बन सकता है और अंततः हताशा का कारण बन सकता है।

इसके अलावा यह अभिनिर्धारित किया गया कि न्यायालय को एक उदार व्याख्या अपनानी चाहिए जो अधिनियम के उद्देश्य की उपलब्धि को आगे बढ़ाती है। पदोन्नति के अवसरों में3% आरक्षण से इनकार करने के लिए राज्य द्वारा सुझाई गई व्याख्या स्पष्ट रूप से अधिनियम के उद्देश्य को विफल कर देगी। यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 38 और 41 में निहित निर्देशक सिद्धांतों के अधिदेश के विपरीत भी होगा।

.

(पैरा 14)

श्रीमती अंजुअरोरा, एडवोकेट, के साथ

श्रीमती अदिति गिरधर, एडवोकेट, के लिए *याचिकाकर्ता.*

रणधीर सिंह, अदल: ए. जी। हरियाणा, के लिए *प्रतिवादी*

MUKUL MUDGAL, CJ

(1) यह रिट याचिका विकलंग सभा, हरियाणा, सिरसा द्वारा दायर की गई है, जिसका पंजीकृत कार्यालय 404, राम गली, कीर्ति नगर, सिरसा में है, इसके अध्यक्ष बालजीत राज के माध्यम से, जो हरियाणा राज्य के शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों का एक संघ है। इस याचिका में प्राथमिक चुनौती हरियाणा सरकार की नीति को दी गई है, जिसने दिव्यांगजन (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के तहत दावा किए गए विकलांग कर्मचारियों को पदोन्नति के लाभ से वंचित कर दिया था (इसके बाद संक्षिप्तता को "अधिनियम" कहा जाता है).

(2) (2) रिट याचिका में उठाई गई मुख्य शिकायत विकलांग व्यक्तियों को पदोन्नति के रास्ते में 3% कोटा से इनकार करने से संबंधित है। याचिकाकर्ता का मुख्य जोर इस तथ्य पर है कि केंद्र सरकार

भी पदोन्नति के अवसरों में 3% कोटा प्रदान करती है जैसा कि अनुलग्नक पी-2 से स्पष्ट है जो कार्मिक, लोक शिकायत मंत्रालय और कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली से एक याचिकाकर्ता को संबोधित संचार से स्पष्ट है और उक्त संचार का प्रासंगिक हिस्सा इस प्रकार हैः -

"(i) विभाग पदोन्नति कोटा में एससी उम्मीदवारों के लिए आरक्षण 15% है% |

(ii) विभागीय पदोन्नति कोटे में ओबीसी उम्मीदवारों के लिए कोई आरक्षण नहीं है।

(iii) विभागीय में शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण पदोन्नति कोटा 3% है%.

(iv) आपके अनुप्रयोगों के बिंदु iv के संदर्भ में, यह चिंता का विषय है श्री ए.के. श्रीवास्तव, यूएस (Estt.D) और इस का CPIO विभाग. तदनुसार, आपका आवेदन स्थानांतरित किया जा रहा है श्री ए.के. श्रीवास्तव, यूएस (एस्ट. डी) और भेजने के लिए सीपीआईओ आप इस मामले में जवाब दें "(आपूर्ति पर जोर).

(३) भारत सरकार के कार्मिक विभाग मंत्रालय, नई दिल्ली ने 29 दिसंबर, 2005 को एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया है, जिसका भी हवाला दिया गया है। ज्ञापन का प्रासंगिक खंड इस प्रकार हैः

"मौजूदा निर्देशों को समेकित करने, उन्हें विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के अनुरूप बनाने और प्रक्रियात्मक मामलों सहित कुछ मुद्दों को स्पष्ट करने के लिए, भारत सरकार के तहत पदों और सेवाओं में विकलांगों (शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों) के लिए निम्नलिखित निर्देश जारी किए जाते हैं। ये निर्देश इस विषय पर अब तक जारी किए गए सभी पिछले निर्देशों का स्थान लेंगे।.

2. आरक्षण की मात्रा: —

(i) प्रत्यक्ष भर्ती के मामले में तीन प्रतिशत रिक्तियां समूह ए बी सी और डी पदों के लिए विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित किया जाएगा, जिनमें से प्रत्येक का एक प्रतिशत आरक्षित होगा (i) अंधापन या कम दृष्टि से पीड़ित व्यक्तियों के लिए, (ii) सुनवाई हानि और (iii) लोकोमोटर विकलांगता या सेरेब्रल प्रत्येक विकलांगता के लिए पहचाने गए पदों में पक्षाघात;

(ii) पदोन्नति के मामले में रिक्तियों का तीन प्रतिशत समूह डी, और समूह सी पोस्ट जिसमें तत्व है प्रत्यक्ष पुनरावृत्ति, यदि कोई हो, 75% से अधिक नहीं होगी विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित जिनमें से एक प्रतिशत प्रत्येक से पीड़ित व्यक्तियों के लिए आरक्षित किया जाएगा [मैं अंधापन या कानून दृष्टि.~ii) हीयाअंगूठीएलटी तथा

(iii) <u>लोकोर्नोटर विकलांगता या सेरेब्रल पाल्सी पदों में प्रत्येक विकलांगता के लिए पहचाना गया.</u> (जोर दिया गया).

*** *** ***

(4) (4) यह प्रस्तुत किया गया है कि अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों की श्रेणी में भी हरियाणा में ही ऐसे कर्मचारियों को पदोन्नति पर आरक्षण दिया जा रहा है।.

(5) (5) उत्तरदाता हरियाणा राज्य ने एक रुख अपनाया है कि विकलांग व्यक्तियों की प्रारंभिक भर्ती के लिए पदों के आरक्षण के लिए अधिनियम में प्रावधान हैं जैसा कि अधिनियम की धारा 32 और 33 से स्पष्ट है, लेकिन पदोन्नति में विकलांगों के लिए आरक्षण के लिए अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं है। यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि चूंकि राज्य सरकार ने विकलांगों के लिए नियुक्ति के समय 3% आरक्षण का प्रावधान पहले ही कर दिया है, इसलिए पदोन्नति में ऐसा आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। इस उद्देश्य के लिए मुख्य सचिव द्वारा हरियाणा सरकार को 23 दिसंबर, 2002 को जारी पत्र पर भरोसा करने की मांग की गई है। विचाराधीन पत्र का प्रासंगिक भाग इस प्रकार हैः: —

> "सर, मुझे आपके पत्र संख्या 2279 / H-3 / SZ / 2002 का उल्लेख करने के लिए निर्देशित किया गया है ऊपर दिए गए विषय पर और आपको सूचित करने के लिए कि कोई नहीं है कक्षा III और IV में पदोन्नति में आरक्षण प्रदान करने की आवश्यकता है शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए पद.
>
> आपका विश्वास,
>
> एसडी/ . • •
>
> महासचिव प्रशासन के तहत, *के लिए* सरकार के मुख्य सचिव हरियाणा "".

(6) (6) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने जी. एम. के माध्यम से दिल्ली उच्च न्यायालय के भारतीय संघ के फैसले पर भरोसा किया। उत्तर रेलवे बनाम जगमोहन सिंह आदि, जहां कानून का निम्नलिखित प्रस्ताव निर्धारित किया गया थाः -: —

> "18. दिव्यांगता अधिनियम की धारा 33 और 47 को एक साथ पढ़कर यह व्याख्या करते हुए कि इन प्रावधानों के लायक हैं, हमारी राय है कि विकलांग व्यक्ति पदोन्नति में भी आरक्षण के हकदार होंगे यदि पदोन्नति समूह सी और डी पद पर है।"".

(7) हमारे विचार में अधिनियम की धारा 47 एक महत्वपूर्ण प्रावधान है के रूप में पढ़ता है: —

47. सरकारी रोजगार में गैर भेदभाव —

(1) कोई भी प्रतिष्ठान रैंक में कमी या कमी नहीं करेगा, ए कर्मचारी जो अपनी सेवा के दौरान विकलांगता प्राप्त करता है :

बशर्ते कि, यदि कोई कर्मचारी, विकलांगता प्राप्त करने के बाद उपयुक्त नहीं है जिस पद के लिए वह जा रहा था, उसे किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित किया जा सकता था समान वेतनमान और सेवा लाभ के साथ पोस्ट;

बशर्ते कि यदि किसी पद के लिए कर्मचारी को समायोजित करना संभव नहीं है, तो उसे तब तक अतिरिक्त पद पर रखा जा सकता है जब तक कि कोई उपयुक्त पद उपलब्ध न हो या वह सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त न कर ले, जो भी पहले हो।.

(2) किसी व्यक्ति को केवल उसकी अक्षमता के आधार पर किसी भी पदोन्नति से इनकार नहीं किया जाएगाः

बशर्ते कि उपयुक्त सरकार, किसी भी प्रतिष्ठान में किए गए कार्य के प्रकार को ध्यान में रखते हुए, अधिसूचना द्वारा और ऐसी शर्तों के अधीन, यदि कोई हो, जो ऐसी अधिसूचना में निर्दिष्ट किया जाए, किसी भी प्रतिष्ठान को इस धारा के प्रावधानों से छूट दे सकती है, (emphasis supplied).

.

(8) धारा 47 (2) का यह अर्थ नहीं लगाया जा सकता कि विकलांग व्यक्तियों को केवल सेवा में प्रवेश के प्रारंभिक चरण में ही रोजगार दिया जाए। अधिनियम का उद्देश्य स्पष्ट है और पदोन्नति सहित कैरियर की प्रगति के लिए समान अवसर स्पष्ट रूप से विधायी अधिदेश है। उक्त प्रावधान का कोई अन्य अर्थ देने से क़ानून का उद्देश्य विफल हो जाएगा। अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों के प्रासंगिक भाग को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

(i) राज्य की जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए विकलांगों की रोकथाम, अधिकारों की सुरक्षा, का प्रावधान चिकित्सा देखभाल, शिक्षा, प्रशिक्षण; रोजगार और विकलांग व्यक्तियों का पुनर्वास ;

(ii) विकलांग व्यक्तियों के लिए बाधा मुक्त पर्यावरण का निर्माण करनाः;

(iii) *विकास लाभों, वीजा-गैर-विकलांग व्यक्तियों को साझा करने में विकलांग व्यक्तियों के खिलाफ किसी भी भेदभाव को दूर करने के लिए;;*

(iv) दुरुपयोग और शोषण की किसी भी स्थिति का मुकाबला करने के लिए विकलांगों के साथ ;

(v) कार्यक्रमों और सेवाओं के व्यापक विकास और विकलांग व्यक्तियों के लिए अवसरों के समानीकरण के लिए एक कानून निर्धारित करना; और

(vi) (vi) सामाजिक मुख्यधारा में विकलांग व्यक्तियों के एकीकरण का विशेष प्रावधान करना।(emphasis supplied)..

(9) उक्त उद्देश्यों और कारणों के उपखंड (i) और (v) अधिक महत्वपूर्ण हैं क्योंकि यह राज्य से विकलांग व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने की अपेक्षा करता है। यह उन अवसरों के समानीकरण पर भी जोर देता है जिन्हें केवल भर्ती के प्रारंभिक चरण में प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यदि राज्य की याचिका को स्वीकार किया जाता है और परोपकारी कानून को एक सीमित अर्थ दिया जाता है, तो यह प्रारंभिक भर्ती स्तर पर विकलांगों के ठहराव का कारण बन सकता है और अंततः हताशा का कारण बन सकता है। इस प्रकार हम जी. एम. के माध्यम से भारत संघ में उपरोक्त उद्धृत निर्णय में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से सम्मानपूर्वक सहमत हैं और दोहराते हैं। उत्तर रेलवे बनाम एस. जगमोहन सिंह, डब्ल्यूपी नं. 1.8 2004 का 1.8 दिनांक 7 दिसम्बर, 2005..

(10) संसद ने विधान द्वारा विकलांगों को सांकेतिक प्रारंभिक प्रतिनिधित्व देने का इरादा नहीं किया था, लेकिन पदोन्नति के माध्यम से कैरियर प्रगति के लिए पूर्ण अवसरों के साथ रोजगार प्रदान करने का इरादा था।.
उपरोक्त के आलोक में, यह स्पष्ट है कि हरियाणा राज्य द्वारा अपनाए गए अर्थ को देने से अधिनियम का उद्देश्य विफल हो जाएगा। यह कानून का एक स्थापित सिद्धांत है कि "रोजगार" शब्द में पदोन्नति शामिल है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने अजीत सिंह-इल और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य (1) के मामले में पैरा 22 में पदोन्नति को अपने दायरे में शामिल करने के लिए "रोजगार" शब्द को परिभाषित किया हैःपीठ ने कहा, "इस अदालत द्वारा बार-बार यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अनुच्छेद 16 का उपखंड (1) अनुच्छेद 14 का एक पहलू है और इसकी जड़ें अनुच्छेद 14 से जुड़ी हैं। उक्त उपखंड अनुच्छेद 14 में व्यापकता को निर्दिष्ट करता है और संवैधानिक अर्थों में राज्य के तहत किसी भी पद पर रोजगार और नियुक्ति के मामलों में "समान अवसर" की पहचान करता है। 'रोजगार' शब्द व्यापक होने के कारण, इसमें कोई विवाद नहीं है कि यह अपने (पुराने, प्रारंभिक

स्तर के स्तर से ऊपर के पदों पर पदोन्नति के पहलू) के भीतर लेता है। भर्ती, अनुच्छेद 16 (1) प्रत्येक कर्मचारी को अन्यथा पदोन्नति के लिए पात्र या जो विचार के क्षेत्र के भीतर आता है, पदोन्नति के लिए "विचार" किए जाने का मौलिक अधिकार प्रदान करता है। यहाँ समान अवसर का अर्थ है पदोन्नति के लिए "विचार" किए जाने का अधिकार। यदि कोई व्यक्ति पात्रता और क्षेत्र मानदंडों को पूरा करता है, लेकिन पदोन्नति के लिए विचार नहीं किया जाता है, तो पदोन्नति के लिए "विचार" किए जाने के उसके मौलिक अधिकार का स्पष्ट उल्लंघन होगा, जो उसका व्यक्तिगत अधिकार है।समान अवसर पर आधारित पदोन्नति और इस तरह की पदोन्नति से जुड़ी 'वरिष्ठता' अनुच्छेद 16 के तहत मौलिक अधिकार के पहलू हैं(1). जोर दिया गया)

.

(11) इसी प्रकार संघ लोक सेवा आयोग बनाम गिरीश जयंती लाल वाघेला और अन्य (2) में माननीय उच्चतम न्यायालय ने फिर से "रोजगार" शब्द की व्याख्या इस प्रकार की:

"अनुच्छेद 16 जो मौलिक अधिकारों से संबंधित संविधान के भाग I में स्थान पाता है, यह उपबंध करता है कि राज्य के अधीन किसी पद पर रोजगार या नियुक्ति से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। अनुच्छेद 16 का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक कार्यालयों में अवसर और रोजगार की समानता के लिए संवैधानिक अधिकारों का सृजन करना है। "रोजगार" या "नियुक्ति" शब्द न केवल प्रारंभिक नियुक्ति बल्कि सेवा की अन्य विशेषताओं जैसे पदोन्नति और सेवानिवृत्ति की आयु आदि को भी शामिल करते हैं। (emphasis supplied).

:

(12) यहां तक कि भारत सरकार ने कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली के माध्यम से विभागीय पदोन्नति में विकलांगों के लिए 3% की सीमा तक पद आरक्षित किए हैं। उपरोक्त मंत्रालय द्वारा याचिकाकर्ता को दिनांक 5 दिसंबर, 2007 के पत्र के माध्यम से दी गई जानकारी निम्नलिखित प्रभाव से है: -

"(i) विभागीय पदोन्नति कोटा में एससी उम्मीदवारों के लिए आरक्षण 15% है|

(ii) विभागीय पदोन्नति कोटे में ओबीसी उम्मीदवारों के लिए कोई आरक्षण नहीं है।

(iii) शारीरिक रूप से विकलांग कोटा के लिए आरक्षण 3% है|

(iv) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x .

(14) माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित विधि की उपरोक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय को एक उदार व्याख्या अपनानी चाहिए जो अधिनियम के उद्देश्य की प्राप्ति को आगे बढ़ाती है। पदोन्नति के अवसरों में 3% आरक्षण से इनकार करने के लिए राज्य द्वारा सुझाई गई व्याख्या स्पष्ट रूप से अधिनियम के उद्देश्य को विफल कर देगी। यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 38 और 41 में निहित निर्देशक सिद्धांतों के अधिदेश के विपरीत भी होगा जो निम्नानुसार हैः -

अनुच्छेद 38-लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित करने के लिए राज्य। राज्य एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था को प्रभावी ढंग से सुरक्षित और संरक्षित करके लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को सूचित करेगा।.

(२) राज्य, विशेष रूप से आय में असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा, और न केवल व्यक्तियों के बीच, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले या विभिन्न छुट्टियों में लगे लोगों के समूहों के बीच भी स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को खत्म करने का प्रयास करेगा। "

अनुच्छेद 41-कुछ मामलों में काम करने, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार। राज्य, अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमाओं के भीतर, बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी और विकलांगता के मामलों में और अभाव के अन्य मामलों में काम करने, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता प्राप्त करने के लिए प्रभावी प्रावधान करेगा। "

(15) इस निर्णय के निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए, रिट याचिका की अनुमति दी जाती है। हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव के लिए अवर महासचिव प्रशासन द्वारा 23 दिसंबर, 2002 को जारी पत्र को तदनुसार रद्द कर दिया गया है। हम उत्तरदाताओं को कार्मिक मंत्रालय द्वारा दिनांक 20 नवंबर, 1989 (अनुलग्नक पी-5) द्वारा जारी निर्देशों और दिशानिर्देशों के

अनुसार पदोन्नति देकर विकलांगों के लिए पदोन्नति के लिए 3% पद आरक्षित रखने का भी निर्देश देते हैं। याचिकाकर्ता रुपये की मात्रात्मक लागत का हकदार होगा। 20, 000 का भुगतान आज से चार सप्ताह के बाद नहीं किया जाएगा।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

आदित्य सैनी
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
रेवाडी (**हरियाणा)**